(सुकांत भट्टाचार्य की कविता)

विद्रोह का गीत

बज उठी है क्या समय की घड़ी?
तो आओ आज हम विद्रोह करें
हम सब जो जिसके प्रहरी हैं
उठें पुकार।

उठे तूफ़ान जमीन और पहाड़ों पर
आग सुलगे ग़रीब की हड्डियों में
करोड़ों दस्तकें पहुंचे दरवाज़ों तक,
रहने दें कायरों को।

हमें बाधाओं की परवाह नहीं
परवाह नहीं नुकसानों की
आंखों में युद्ध का दृढ़ समर्थन है
इस आगे बढ़ने को अब
भला कौन रोक सकता है
किसकी हिम्मत है?

वे रोटी नहीं देंगे! नहीं देंगे अन्न!
इस लड़ाई से तुम खुश नहीं हो?
आंखें दिखाने को हम गिनते ही नहीं
नहीं करते परवाह।

शोहरत के मुंह पर ठोकर मारते हैं हम
गढ़ते हैं, हम तो विद्रोह गढ़ते हैं
तोड़ते हैं हाथों की जंजीरें
मरते दम तक।

दिशाओं–दिशाओं में फैल रहा है विद्रोह
अब बैठे रहने का समय बिल्कुल नहीं हैं
खून से लाल हो उठी है
पूर्व दिशा।

फ़ाड़ता हूं, गुलामी की दलीलें फ़ाड़ता हूं
बेपरवाहों के झुंड में होता हूं शामिल
तलाशता हूं, कहां है स्वर्ग की सीढ़ी
कहां है प्राण!

देखूंगा, ऊपर आज भी है कारा
चोटों से गिराऊंगा आकाश के तारे
आखिरी बार झकझोरूंगा
इस दुनिया को
बिखेरुंगा धान।

जानता हूं खून के पीछे
पुकारेगी सुख की बाढ़।

पेज 1 का शेष

मोदी तेरी हवा कहां है ?

गुजरात के 'विकास' का मॉडल कभी मोदी की चुनावी रणनीति में प्रमुख भूमिका निभाता था। धीरे-धीरे इसकी भी पोल-पट्टी खुलती गयी है। लिहाज़ा, अब मोदी के पास सिवाय मौके के मुताबिक पगड़ियां बदलने और लफ़्फ़ाज़ियां करने के कुछ अधिक नहीं बचा है।

दरअसल, आर एस एस के अरबी घोड़े नरेन्द्र मोदी के लिये अपनी नई भूमिका को निभा पाना उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है। इस 'चायवाले' का कार्पोरेट प्रेम किसी से छिपा नहीं है। सत्ता पाने पर यह 'चौकीदार' कार्पोरेट मुनाफ़े की ही चौकीदारी करेगा, न कि जनता के हितों की। काले धन से अपना प्रचार चलाने वाले मोदी से यह उम्मीद करना बेमानी है कि वह काला धन समाप्त करने की दिशा में कोई वास्तविक पहल करना चाहेगा।

मोदी के आने से वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ है वह भी मोदी के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा। मोदी की उम्मीद इस पर टिकी थी कि कांग्रेस के नाकारा सिद्ध होने से भारतीय राजनीति में जो जगह बनेगी उससे उनकी हवा को तूफ़ान बनाया जा सकेगा। पर उनके दुर्भाग्य से इस बीच आम आदमी पार्टी का उदय हो गया है। इससे कांग्रेस की खाली जगह खाली नहीं रह गयी। लिहाज़ा तूफ़ान तो बना नहीं, अब मोदी की हवा भी रुकती नज़र आ रही है।

'आप' पार्टी का गुजरात का 5 दिवसीय रोड शो निश्चित रूप से मोदी की मुश्किलों को और बढा गया है येगा ही। गौरतलब है कि देर तक मोदी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी तय नहीं हो पाने के है। पीछे एक डर यह भी काम कर रहा है कि निर्वाचन क्षेत्र जाहिर करते ही 'आप' द्वारा वहां कड़ी मुहिम शुरू हो जायेगी। तब मोदी के लिये 'आप' के सवालों से मुंह छिपाना उत्तरोत्तर मुश्किल होता जायेगा। यानी, केजरीवाल के शब्दों में तब आम वोटर भी पूछने लगेगा–बता मोदी तेरी हवा कहां है ?

टी. वी. चैनलों पर भ्रष्टाचार का मछली बाज़ार

असर के नाम पर कैमरे पर पकड़े गये कर्मचारियों का निलम्बन एवं उनपर की गयी अनुशासनिक एवं आपराधिक कार्यवाही शामिल होती है। वास्तव में यह असर कुछ वैसा ही है जैसा जलती शमा के सामने जलते पतंगों का होता है। जब तक भ्रष्टाचार व्यवस्था की शमा जलती रहेगी तब तक उस पर मंडराने वालों की संख्या कम नहीं हो सकती।

मीडिया चैनलों को इस सवाल पर भी घेरा जाना चाहिये कि रिलायंस, डी एल एफ, सहारा, किंगफ़िसर सारदा, जिंदल जैसे हज़ारों कार्पोरेट घोटाले जो देश के एक-एक व्यक्ति की जेब खाली करने के दोषी हैं, उनके रडार पर होते क्यों नहीं। हों भी कैसे ? इन्हीं की पूंजी से तो ये चैनल चलते हैं और इनके बड़े-बड़े सम्पादक करोड़ों की सालाना पगार लेते हैं। जनता के गुस्से को महज़ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मोड़कर टी.वी. चैनल कार्पोरेटों की ओर से ध्यान बंटाये रखने का महत्वपूर्ण दायित्व भी आसानी से निभा जाते हैं। यहां तक कि रोज़ राजनीतिकों को कठघरे में खड़ा करने वाले ये चैनल उनकी कार्पोरेटों के घोटलों के प्रति चुप्पी पर सवाल खड़ा करने की हिम्मत नहीं करते।

अगली बार जब आप किसी चैनल को ऐसा स्टिंग आपरेशन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में, एक निर्णायक पहल के रूप में महिमा मंडित करते देखें तो टी.वी. एंकर की भंगिमाओं पर न जाइये। यह भी देखिये कि वह चैनल किस कार्पोरेट का उल्लू सीधा कर रहा है।

पेज 8 का शेष

विज्ञापनों की नाव से चुनावी वैतरणी पार करेंगे हुड्डा ?

सरकार ने शिक्षा विभाग से भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता को दूर करके इसे चुस्त दुरुस्त बनाने की अपेक्षा सर्वशिक्षा अभियान के नाम से लूट का एक नया रास्ता जरूर खोल दिया। सैंकड़ों करोड़ सालाना बजट के इस अभियान की खूबी यह है कि इसमें कोई भी कर्मचारी स्थाई नहीं है। जितने दिन जो कर्मचारी व अधिकारी यहां रहे, मौज करे, लूटे-खाये और आगे चल दे। जब कभी कोई ऑडिट वाला आये तो सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी वहां से पार हो चुका होता है। इसलिये किसी खरीद एवं खर्च के लिये किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

पुस्तक घोटाला भी हुड्डा सरकार का एक बड़ा कारनामा रहा है। सरकारी स्कूलों को करोड़ों रुपये खर्च करके पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। किसी भी वर्ष ये सही समय पर नहीं दी गयीं परन्तु वर्ष 2013-14 में तो सरकार ने कमाल ही कर दिया। पूरा डेढ सेमेस्टर बीत जाने के बाद बच्चों को किताबें दी गयीं। समझना कोई मुश्किल नहीं कि ऐसे में क्या तो बच्चों ने पढा होगा और क्या अध्यापकों ने पढाया होगा।

जहां तक बात है अध्यापकों की तो राज्य भर में गत दसियों वर्ष से अध्यापकों व प्राध्यापकों की भर्ती नहीं हुई है। इसके चलते स्कूलों में 30000 से अधिक अध्यापकों और 5000 के करीब (कॉलेज) प्राध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। इससे पूर्व चौटाला राज में जो कुछ अध्यापक भर्ती किये गये थे उनकी हकीकत पिछले दिनों उस वक्त सामने आ गयी थी जब अदालत ने ग़लत ढंग से भर्ती करने के आरोप में चौटाला जी को उनकी पूरी मंडली सहित जेल भेज दिया था।

स्कूल अध्यापक की नौकरी पाने के लिये बीएड व डीएड की डिग्री पाना अनिवार्य है। तो सरकार के सहयोग से कुछ शिक्षा 'उद्यमियों' ने उक्त डिग्रियां बेचने का धंधा ही शुरू कर दिया। अकेले फ़रीदाबाद ज़िले में दर्जनों ऐसी दुकानें खुली हैं। मज़े की बात यह है कि इन दुकानों को बाकायदा एम डी यू द्वारा नियुक्त जांच समितियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इनके पास बीएड व डीएड की पढाई

पेज 8 का शेष

पुलिस के मेल से जनता का निकलता तेल

यह काम एच डी एफ सी, आई सी आई सी आई व सिटी बैंकों के जरिये ही अधिक होता है। कहने को पुलिस कह सकती है कि इतने वैज्ञानिक तरीके से चलाये जाने वाले इस जुए का उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन यह सरासर ग़लत है। जहां-जहां यह धंधा चलता है, वहां के बच्चे-बच्चे को इसका पता होता है, यदि पता ही नहीं चलेगा तो फ़िर रोज़ाना नये-नये शिकार कहां से और कैसे फ़ंसेंगे ? जाहिर है ऐसे में पुलिस को भी पूरी जानकारी रहती है। हां बात केवल इतनी है कि इनके विरुद्ध कार्यवाही करने में अपनी उर्जा व समय 'बर्बाद' करने की अपेक्षा बैठे-बिठाये इनसे चुपचाप हफ़्ता वसूली इन्हें कहीं लाभदायक एवं सुविधाजनक लगती है।

अपनी इस काली कमाई को उचित ठहराते हुए पुलिस वाले प्राय: यह तर्क भी देते हैं कि यह कोई बहुत घातक क्राइम नहीं है; फिर इसमें कोई शिकायतकर्ता भी तो नहीं है; खेलने व खिलाने वाले दोनों राज़ी हैं तो पुलिस को क्या जरूरत पड़ी ख्वामखां में अपना काम बढाने की। लेकिन ये तर्क बिल्कुल बेहूदा हैं। जुआ, शराब का धंधा और वेश्यावृत्ति जैसे अपराध समाज को घुन की तरह तो खाते ही हैं, साथ में हत्या, आत्महत्या, चोरी व डकैती जैसे अपराधों को भी जन्म देते हैं।

धंधे की भीतरी जानकारी रखनेवाले भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि एनआईटी क्षेत्र में चलने वाले प्रति कैसीनों से 25-30 हज़ार की मंथली, सेक्टरों में 30-35 हज़ार व थाना सारण के क्षेत्र में 15 से 17 हज़ार की मंथली एडवांस में पुलिस को पहुंच जाती है। थाना एनआइटी पुलिस से सेटिंग कराने का ज़िम्मा सुखदयाल और बिल्डर अजय कथूरिया का है तो थाना सारण का ज़िम्मा राकेश चक्की वाले के पास है जो खुद भी अपना ऑनलाइन कैसीनो थाने के ऐन सामने जनता कॉलोनी में चलाता है। थाना एनआईटी के गांव फतहपुर चंदीला, गांधी कॉलोनी तथा 5 नम्बर के सी व के ब्लाक में अधिकांश कैसीनो सक्रिय हैं तथा पुलिस की पूरी जानकारी में हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ज़िला पुलिस प्रमुख चावला इस लायक नहीं हैं कि वे इस पूरे धंधे की जानकारी लेकर इसे रोक सकें या वे खुद भी इस काली कमाई में हिस्सेदार हैं ?

उधर हिमांशु आत्महत्या मामले में, खबर लिखे जाने तक पुलिस ने किसी भी कैसीनो संचालक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। इससे दुखी शहर के मौजिज शहरी मुख्यमंत्री तथा अन्य नेताओं से मिले हैं। इन लोग़ों ने मुख्यमंत्री को साफ़-साफ़ कह दिया है कि मौजूदा चुनाव में कांग्रेस को वोट तभी मिलेंगे जब वह इन कैसीनो संचालकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करके शहर को इनसे मुक्ति दिलायेंगे।

अरबपतियों के मुकाबले 'आप' ने उतारा डागर

'आप' का कोई सांगठनिक ढांचा तो है नहीं जो मर्ज़ी सदस्य बन जाओ। जब इस तरह से खुली सदस्यता मिलेगी तो सत्ता व पूंजी के दलालों की घुसपैठ से कैसे बचा जा सकता है ? यह तो अभी मौका नहीं मिला वरना दिल्ली के 28 'आप' विधायकों में सें दसियों बिन्नी की तर्ज पर बिकने को तैयार घूम रहे हैं। 'आप' में जिस तरह से सदस्यता के नाम पर भीड़ एकत्र की जा रही है, उसमें इस तरह के विरोध व टूटन होना स्वाभाविक ही है। किसी को टिकट दे लो, न मिलने वाले तो विरोध करेंगे ही।

फ़रीदाबाद से पुरूषोत्तम डागर का चयन 'आप' के लिये यह शुरूआत है। 'आप' के ज़िला संयोजक आभास चंदीला ने इस संवाददाता को बताया कि टिकट आवंटन को लेकर पार्टी के भीतर इस तरह के छोट-मोटे विवाद तो चलते ही रहते हैं जिन्हें अब पूरी तरह से सुलझा लिया गया है और सभी मिलकर डागर को जितायेंगे।

कराने लायक भवन, पूरा स्टाफ़ तथा अन्य आवश्यक साज़ों-सामान व पुस्तकालय आदि मौजूद हैं। लेकिन वास्तव में इनके पास न तो पर्याप्त भवन होता है और न ही पढाने वाला स्टाफ़, बाकी साज़ो-सामान का तो मतलब ही क्या। और तो और ऐसे किसी भी तथाकथित कॉलेज के पास निर्धारित योग्यता का प्रिंसिपल तक नही है। दूसरी मजेदार बात यह है कि ये दुकानें अपने ग्राहकों को सीधे-सीधे डिग्रियां नहीं बेच सकतीं। कौन अभ्यार्थी किस दुकान से डिग्री खरीदेगा इसका निर्णय भी एम डी यू ही करती है। इस काम के लिये एम डी यू को बाकायदा फ़ीस तथा सम्बंधित कर्मचारियों को रिश्वत दी जाती है। जो अभ्यार्थी नियमित रूप से इन तथाकथित कॉलेजों के रोज़ाना धक्के खाना नहीं चाहते, अपना समय व यात्रा-भाड़ा बचाना चाहते हैं, उनसे गैरहाज़िर रहने की फ़ीस अलग से वसूली जाती हैं। क्या मतलब है ऐसी 'पढाई' व डिग्री का हुड्डा साहब ?

जिस तरह की पढ़ाई उक्त शिक्षण संस्थानों में हो रही है, उसके चलते, 'पढे-लिखे' अनपढों की फ़ौज राज्य में तैयार हो रही है। अध्यापकों की भर्ती हेतु रखी जाने वाली पात्रता परीक्षा बमुश्किल एक चौथाई अभ्यर्थी भी पास नहीं कर पाते। लेकिन पास नहीं कर पाने वालों को तसल्ली इस बात से है कि पास होने वाले भी तो उन्हीं की तरह ठाली बेरोज़गार घूम रहे हैं; पास होकर उन्होंने कौन सा तीर मार लिया ?

राज्य भर में जो कुछ थोड़ी बहुत पढाई हो रही है, वह मंहगे प्राइवेट स्कूलों और थोड़े से केन्द्रीय विद्यालयों में हो रही है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय स्कूल सस्ते और अच्छे तो हैं पर वे राज्य भर के बच्चों को तो नहीं पढा सकते। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब इसी शहर में केन्द्रीय स्कूल ढंग से पढाई करा सकते हैं तो हरियाणा सरकार के स्कूलों में क्या आग लग रही है, इनमें क्यों पढाई नहीं हो पा रही ? जाहिर है सरकारी भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद के चलते पूरे शिक्षा विभाग का सत्यानाश सरकार ने कर दिया है और करती जा रही है। किसी देश व समाज का सत्यानाश करना हो तो उसकी शिक्षण व्यवस्था को तबाह कर दो, बस फ़िर बाकी काम तो स्वत: हो जयेगा। यह काम पहले चौटाला सरकार व अब हुड्डा सरकार ने बखूबी कर दिखाया है। अब इनका पूरा ध्यान उन निजी स्कूलों को उजाड़ने पर भी लगा है जो शिक्षा के नाम पर भले ही व्यापार कर रहे हैं पर बच्चों को किसी लायक बना तो रहे हैं।